श्री रामेश्वर सिंह : हमसे हमेशा यही आशा रखिए ।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया :

Lastly, regarding the tea industry and tea cultivation, the Government is quite serious about this matter and we are considering to give some relief to the tea industry so that they can develop this cultivation and may get relief to export tea to foreign countries. I am thankful to the Members for their contribution.

श्री भोला प्रसाद : मैंने पूछा था कि खेतिहर मजदूरों . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) : ठीक है, उन्होंने जवाब दे दिया ।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : यह खेत-मजदूरों पर भी लागू होता है ।

श्री भोला प्रसाद : "भी लागू" का क्या मतलब हुआ ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मैंने बताया अभी आप के सामने छठी पंचवर्षीय योजना विचारार्थ थी उसमें यह बात कही गई थी ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1981-82, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill. There are no amendments

Clause 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SAWAI SINGH SISODIA: Sir, I move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जरा ठहरिये । मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): If you want to speak on the Third Reading, you should give me in writing that you want to speak.

श्री शिव चन्द्र झा : नहीं, मैंने नाम दिया था . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I do not have it before me.

श्री शिव चन्द्र झा : थर्ड रीडिंग के लिए नाम दिया हुआ है । यह बहुत बेइंसाफी हो रही है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): You want to speak on the next Bill also. We have to finish the next Bill before six o'clock.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: That is not the point.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE INCOME TAX (AMENDMENT) ORDINANCE, 1981 (NO. 8 OF 1981)

II. THE INCOME TAX (SECOND AMENDMENT) BILL, 1981

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now, we take

up the Statutory Resolution. Dr. Bhai Mahavir, Shri Jagdish Prasad Mathur, Shri Kalraj Mishra, Shri Lakhan Singh, Shri Pyarelal Khandelwal, Shri Ashwani Kumar, Shri Ram Lakhan Prasad Gupta, Shri Hukmdeo Narayan Yadav, Shri Shiva Chandra Jha. Mr. Minister.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Bihar): I am here to speak on the Resolution.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I have called you.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: That is not the way of calling. You can see that I am standing here. There is no question of calling the Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): You should be prepared to speak.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: But there are certain things to be clarified.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): All the Members cannot speak in all the matters. I may point out to the House that your leader in the Business Advisory Committee agreed to a particular time. They agreed that this Bill will be disposed of in one hour.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: It does not mean that the time is limited. There is the second reading and there is the third reading.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): We have got the Income-tax (Second Amendment) Bill. Do you know what time has been fixed? Your leader has also agreed for one hour.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: That does not matter. There are the stages earmarked, first stage, second stage and third stage. Whether it is one hour or two hours, it does not matter.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): But the entire Bill is for one hour.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: But there is the first reading, the second reading and the third reading

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I agree. But on the Statutory Resolution, you will get only two minutes. We have to adjust within one hour. Anyway, please move your Resolution.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Sir, I beg to move the following Resolution:

"That this House disapproves the Incomt-Tax (Amendment) Ordinance, 1981 (No. 8 of 1981) promulgated by the President on the 11th of July, 1981."

श्रीमन्, यह सरकार टैक्सेशन के लिए भी आर्डिनेंस लाती है । आर्डिनेंस का राज है । जब दो मिनट हो जायें तो बता दीजिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I will give you reasonable time.

श्री शिव चन्द्र झा : सरकार गलत काम करती है । सेशन आने ही वाला था । यह प्रक्रिया जो आपका डेमोक्रेटिक फार्म है उस पर आघात करती है । टेक्सेशन के मुताबिक आपकी नीति वैज्ञानिक नहीं है । एल० के० झा कमेटी की रिकमेंडशन्स को क्या आपने इम्प्लीमेंट किया है ? चौकसी कमेटी की रिकमेंडेशन्स को कहां तक इम्प्लीमेंट किया। चोकसी कमेटी की रिकमेंडेशन्स को इम्प्लीमेंट करने की आप सोच रहे हैं। रीगन एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे वैलफेयर मेजर्स को खत्म करके टैक्सेज को लोअर करके प्राइवेट एन्टरप्राइज को बढ़ावा दिया, वही नीति इन्होंने अखितयार की । वह बात थोड़ी देर के लिए इर्रेलेवेन्ट हो जाती है । इन्टरनेशनल मोनीटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की ऐसी चपेट में आये हैं कि रुपए का डिवेल्युशन और साथ-साथ जो अन्दर में वह चाहते हैं वह करने के लिए ये तैयार हैं । सारी प्लानिंग को भी स्कटल करने का सुझाव उधर से आता है in the name of structural adjustments.

रुपए का डिवेल्युएशन ही नहीं, मगर एमेंशियल सर्विसेज और वर्कर्स के राइट्स को खत्म करने का प्रस्ताव भी आता है कि यह सब मानोगे तब पैसा मिलेगा और ये सब करने जा रहे हैं। यह परिस्थिति हो गयी है । केपिटलिज्म का गढ़ है अमरीका और जो नीति वह अखितयार करता है कैपिटलिज्म को बनाये रखने के लिए वही नीति यहां पर अखितयार की जाती है टैक्सेशन के मुताबिक । कहने के लिए कहते हैं कि हाम काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी नीति से ऐसा लगता नहीं । टैक्सइवेजन की बात ले लीजिए । बियरर बांड्स के जरिए ब्लैक मनी कितना मिला ? कहने का मतलब यह है कि प्रिंसिपल आफ टैक्सेशन का दर्शन आपका साफ नहीं है । तफसील में जाने की जरूरत नहीं है । हमारे देश में जहां पर ग्लेरिंग डिस्पेरिटी है, एक तरफ बड़े बड़े हैं और दूसरी तरफ खेतिहर मजदूर हैं, जो देश की आधी आबादी हैं, लगभग 48 परसेंट और गरीबी की रेखा के नीचे हैं, ऐसे मुल्क में टैक्सेशन की एक नीति और दर्शन होना चाहिये not the principle of what you got but how you got. यह बात मैंने पहले भी रखी है कि पैसा कैसे आया। काला धन अगर मुनाफाखोरी से हो, स्मगलिंग से हो तो राष्ट्र के लिए हमको दे दो । प्रतिभा प्रतिष्ठान से तो आप टैक्नीकली निकल गये कि कुछ नहीं किया । यह गांधी का देश है, जवाहर का देश है, नैतिकता का तकाजा है कि फीज करो अन्तुले की एसेट्स को, सारी को फीज करिए, कन्ट्रोल करिये, सारे की जांच हो । आप तो सब खुला छोड़ रहे हैं जो धन्धा किया उसने करोड़ों का क्योंकि आप टेक्नीकली बच रहे हैं । यह उनकी नीति है । जिनके पास पैसा है वह तरीके से बच जायेंगे, कह देंगे कि जितना देना था उतना दे दिया, अधिक नहीं है कानून के मुताबिक । लेकिन आज भी अखबार में निकला है कि सिनेमा स्टर्स के यहां रेड करने पर आपको सात लाख रुपया या कितना मिला है और कितना अभी मिलना बकाया है । तो आपको पैसा चाहिये यह मैं जानता हूं क्योंकि योजना आपको चलानी है । इसको सारा देश जानता है लेकिन आप को इस देश में पैसे की कमी नहीं है । आपका पैसे को मोबिलाइज करने का तरीका अनसाइंटिफिक है, अवैज्ञानिक है । जो ग्लेयरिंग डिस्पेरिटी है उस पर आप चोट करें और इसके लिए विल टु डू की जरूरत है । आप पार्लियामेंट में नहीं थे जब कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था । उस समय यही विल टु डू की जरूरत थी । अभी जो स्थिति है उसको श्री वेंकटरामन ने बना दिया है उसके कारण की अन्तुले एफेयर होते हैं । इसके लिए भी प्रिविलेज मोशन की जरूरत है ।

एक तो आर्डिनेंस ला कर हो आप जनतंत्र पर कुठाराघात कर रहे हैं और इस बिल के मातहत जो कुछ आप ला रहे हैं यह कोई नई चीज नहीं ला रहे हैं। यह तो टिकरिंग विद दि प्राबलम है। इसके लिए आपको अपने दर्शन को साफ करना होगा। आप को टैक्सेशन लाज की तरफ ध्यान देना होगा। करा धान कैसे हो रिसोर्सेज कैसे मोबिलाइज हों, इस पर ध्यान देना होगा ताकि छठी योजना कामयाब हो। और समाजवाद की बात से तो आपको मतलब नहीं है। छठी योजना हमने खूब देखी है। उसमें कहीं सोशलिज्म वर्ड नहीं है। सिर्फ एक बार आखिर में यह वर्ड आया है। मैं चैलेंज करता हूं कि आप फाइव इयर प्लान के इंट्रोडक्शन में इसको दिखा दें। मैं मैकेनिकल तौर पर नहीं बोल रहा हूं। थर्ड फाइव इयर प्लान का इंट्रोडक्शन जिसने लिखा था उसको आस्था उसमें जरूर थी लेकिन छठा प्लान बनाने वालों की आस्था उसमें नहीं है आज तो सोशलिज्म शब्द का कहना भी हमारे भाइयों को नागवार हो गया है। तो यह आपको मुबारक है और इसी से आप अपनी अर्थ व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। आप इन शब्दों के साथ जो आपने आर्डिनेंस निकाला है उसका पुरजोर विरोध करता हूं और मैं कहूंगा कि टैक्सेशन के मुताल्लिक आप अपने दर्शन को साफ करें और कोई दूसरा विधेयक लायें।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Income-tax Act, 1961, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, this Bill seeks to replace the Income-tax (Amendment) Ordinance, 1981, which was promulgated by the President on the 11th July, 1981. Before outlining the main features of the Bill, I propose to indicate briefly the background in which the Government decided to initiate legislation in this behalf through an Ordinance.

As the hon. Members are aware, the proliferation of black money poses a serious threat to the national economy and it is considered necessary to take effective steps to contain and counter this major social and economic evil. The Government have in recent past taken several legislative and administrative measurs to unearth black money. The present Bill represents another step in the same direction. It came to Government's notice that a substantial amount of black money has been deposited by tax evaders with banks, companies, co-operative societies and partnership firms either in their own name or in benami names. With a view to countering attempts to circulate black money in this manner, it was decided to make a provision in the Income-tax Act to the effect that banks, companies, co-operative societies and partnership firms will repay fixed deposits including interest thereon by account payee cheques or account payee bank drafts where the amount of deposit including interest if any, is Rs. 10,000 or more Banks were given the additional facility to repay the amount by crediting the account of the payee with the banks.

It is hoped that this measure will enable the Income-tax authorities to identify persons who have made such deposits. The Bill as introduced in the Lok Sabha was applicable in cases where an individual deposit made by a depositor, together with interest thereon, was not less than Rs. 10,000 and did not cover cases where the aggregate amount of the deposits made by the depositor exceeded the specified limit. In order to make the relevent provisions more effective, these have been modified to provide that the new section 269T

will apply in all cases where the aggregate amount of the deposits held by a person with a branch of a bank including a co-operative bank or with any other company or co-operative society or firm, either in his own name or in a joint name with any other person, on the date of repayment, along with interest, if any, is not less than Rs. 10,000. The Bill as passed by the Lok Sabha also provides that repayment by a branch of a bank including a co-operative bank can, in the alternative, be made by crediting only a savings bank account or a current account of the depositor. The provisions as so amended will apply prospectively from the date the Bill receives the assent of the President.

The Bill also provides that in the case of a default in making repayment of the term deposits otherwise than in the specified manner, the person responsible for the default will be liable for imprisonment for a term up to 2 years and also for a fine equal to the amount of the deposit.

As the hon. Members would know, the Supreme Court has dismissed the writs filed by certain persons challenging the constitutional validity of the Special Bearer Bonds Scheme. At the time of the hearing of the writ petitions, Government had undertaken to repay the Bonds at the time of the redemption by an account payee cheque or account payee bank draft only. The Bill seeks to make a specific provision in this behalf also.

Sir, this is a short and simple Bill. I hope the hon. Members of this House will give their unanimous support to the Bill.

श्रीमन्, मैं एक मिनट में माननीय झा साहब का भी जवाब देना चाहता हूं। उनका कहना है कि हम देश का मस्तक नीचा करना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश का वर्तमान नेतृत्व देश के मस्तक को हर प्रकार से ऊंचा उठाना चाहता है और देश के गौरव और स्वाभिमान को ज्यादा ऊंचा उठाकर संसार में हमारे देश का नाम ऊंचा उठे, यह प्रयत्न हमारा वर्तमान नेतृत्व कर रहा है। . . . (व्यवधान)

श्री शिव चन्द्र झा : आप बात को डिस्टार्ट मत कीजिए . . . (व्यवधान)

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now, the Resolution and the motion are open for discussion. Mr. Kulkarni, I hope you will conclude in seven minutes.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY (West Bengal): He is the only speaker from our party.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI (Maharashtra): Sir, I will give the maximum co-operation. Actually, Sir, some type of rationality must be there also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): This is the difficulty again. When you ask...

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: You are a presiding officer...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): You are also a presiding officer. What I was pointing out is, it is now 4.35 virtually. At six, we have got Half-an-Hour. We have only one and a half hours in which we have to dispose of this Bill and also another Bill by which a company is being acquired. If you do not want to pass that Bill, I do not know, but the company will not be acquired because the Rajya Sabha could not put its seal.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Look at those benches. Opposition benches are full. If they want to pass the Bill, where are their Members?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I will have no problem. May I point out to you, because after your speech will be over, you will be occupying this chair and you will be managing the show. That I may point out to you.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI (Uttar Pradesh): I draw the attention of the Parliamentary Affairs Minister, Sita Ram Kesri ji. Yesterday, he shifted the burden to the Railway Minister. What about him? I want to know from him. Everyday you throw the burden on somebody; what about yourself?

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Before, Sir,... (*Interruptions*) Mr. Ramakrishnan, don't make it a club here.

SHRI U. R. KRISHNAN (Tamil Nadu): So many times, you are making it a club.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Do not talk loudly. Do not disturb me. You can talk anything you like.

SHRI R. MOHANARANGAM (Tamil Nadu): We are sorry. (*Interruptions*)

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Now, Sir, what is the context in which this Income-tax (Second Amendment) Bill has been brought forward? It is not that this is for the first time that the Government has thought that black money is flourishing in this country. Many Committees were appointed and it has been conclusively proved that there is a parallel economy which is working in this country, which is in vogue in this country and the Government is trying through various measures to eliminate this parallel economy so that inflation will be reduced.

Sir, I would like to suggest, through you, to the Government, particularly, to the hon. Minister of State of Parliamentary Affairs who is now on his legs, that at least my speech should be brought to the notice of the Prime Minister because, ultimately, it is the treasury benches, it is the ruling party, which has to govern this country. You have been elected to govern this country. Sir, today, I read an article in 'The Times of India' by Mr. Girilal Jain. Such a staunch supporter of the Prime Minister has now, it seems, his feet a little bit faltering, in regard to the conviction. He doubts perhaps, with this type of atmosphere, with this type of calibre of the Members of the ruling party, whether the country will be able to come out of the morass whether the Government will be able to stem the rot.

Mr. Minister, you will have to take much care. This is an environment of corruption, as it has been called. This environment of corruption has to be dealt with with strong hands. But Sir, I am very sorry to say that this environment of corruption cannot be dealt with, with strong hands, in this atmosphere, wherein, it seems, they have reached a point of no return. Sir the point is, everywhere, the root-cause of political and bureaucratic corruption is some type of allurements, some type of inducements and some type of trading between boss the party workers. I am not referring particularly to the Antulay affair, because I am fed up with that name. I do not want to talk about that affairs. This has already been discussed. The country knows about it. The whole country knows the pros and cons of this affair. It is for the treasury benches to take a view whether such type of brash and boorish Chief Ministers like Antulays, Gundu Raos and Jagannath Mishras are required, or, whether the Government wants to clean the stables and stand to the image of 'Mr. Clean'.... (*Interruptions*)

SHRI KALPNATH RAI (Uttar Pradesh): What about Sharad Pawar?

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: I do not know whether Mr. Rajiv Gandhi will do that.

Sir, what is happening in Maharashtra? I am bringing it to the notice of the treasury benches. Perhaps, you may not know anything. May be, Sir, similar things may be happening in your State also; I do not know. But I would like to point out about Maharashtra because the Government must know what is happening. They should know how, in my State, support is being obtained from the Assembly Members, Members of Parliament and party workers at a price of favour. This has to be gone into. This is a problem of social importance. This is a question of the survival of democracy. That is why, I would plead with the Government. I hope, the Government will take cognisance of it. Favours are being distributed and loyalties are being obtained at a price. This, Sir, is very dangerous for the democratic functioning of the country. What is this price? I would request the Prime Minister to enquire into this, through the CBI, how many ruling party MLAs have been given permits to work and operate liquor shops, either on their own or through their kith and kin. How many of them have been given agencies? How many of them have been given cement quotas? There is a system in Maharashtra. Each MLA in a district has been allotted a cement quota. He distributes it, along with the Collector. Whatever was stated by the Civil Supplies Minister is only a paper scheme. But I do not know what to say about the MLAs who are responsible for distributing cement. About the Chief Minister's quota enough has been said. So, this type of favour is done. Liquor licences are being given and have already been given to many MLAS and MPs, particularly from the ruling party. There are a few from the opposition party. There are some MLAs and MLCs from the opposition parties who have got this quota, but the do not belong to my party, unfortunately. What I want to say is, we have got deep faith and belief in Mahatma Gandhi's teachings and that is why we have not taken the risk of running these liquor shops for Mr. Antulay. I am saying this because a few days back I met some youngesters who did not support the signature movement for the Chief Minister. They said that enquiries have been started against them, their liquor quotas have been reduced. Such type of bullying and seeking sycophancy, such type of distribution of favouritism is going on. After all, what type of party is being built up? My friend, Mr. Jain said that they will shed their blood, but where is that damn blood? The members of political parties are thriving on all these favours being shown by the Government and you say that the time will come when you will fight for the country. I am not trying to damage the image of your party. This is a lesson for both of us.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Kulkarni, I do not want to disturb you. I am only telling you about the time.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: I am coming to an end. I am very fast just like Rajdhani. So, this is the type of favouritism arranged by Chief Ministers, whether it is Karnataka or it is Maharashtra or any other State. Would you believe that Kerosene agency for Maharashtra is given to an M.P./M.L.A. I do not want to name him today, but in the next session, I warn, I will come out with the name. Rs. 21,000 is the benefit passed on to that M.P., for doing that work? The type of work to be done is liaisoning and lobbying on behalf of the Chief Minister.

यह हलित हो गई है ।

I am not against Mr. Antulay as person. I know Mr. Antulay very well. He is a bright, intelligent boy, a risk-bearing chap, but unfortunately, he has gone on a wrong side. And what is the reason for that? Just now

I was discussing with some friend outside in the lobby. He told me and in a statement of Shri Antulay which has appeared in the Statesman it is said, what can he do? He has to collect money for the party. pass on some portion of money to high command of party. (*Interruptions*). He can deny that. (*Interruptions*). Mr. Patil, do not get nervous. (*Interruptions*).

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI VIJAY N. PATIL): You should speak about Kanti Desai and Padma Desai. This has come up in the Lok Sabha. You should not speak about Antulay like this. (*Interruptions*).

श्री अरविन्द गणश कुलकर्णी : कांति देसाई का मामला तो बहुत पुराना हो गया है। तब आप बच्चे थे।

What I want to say is, it is the high ups in Central Government which is involved in it. Sir, today morning we brought this question of Tapeshwar Singh. There are crores of rupees in the Jeeja Mata Trust. Will Mr. Sisodia first take out the names of persons who have contributed to all the trusts of Mr. Antulay and the trusts of we cooperators in which I am also a trustee. But enquire of everything. Perhaps names have come. I do not want to name my leader also, but the trusts are there. This Jeeji Mata Trust and other trusts are there. They sell liquor. control prices at Rs. 1200. they collect Rs 2600 and Rs. 1000 is collected in the name of trust, in the name of the chairman or in the name of his wife or somebody else. So. Mr. Minister, in the next budget and or immediately get a list of those who have contributed money to these trusts and see whether they have paid any income-tax. That is why I requested that Mr. Venkataraman should be present here. I demand that the "cooperative corruption" which is going on in a very wrong way, should be put an end to. Late Pandit Nehru and Vaikunth Mehta and late Shri Gadgil or Shri Y. B. Chavan, who were leaders of the cooperative movement, would have never dreamt that their successors in the movement would be so corrupt or politically so dangerous. At present, if there is going to be any election in Maharashtra for a cooperative sugar factory, it will be fought with tanks and barrels of guns; it cannot be fought on a democratic basis, because the vested interests are earning money and they are ruling supreme. That is why it has to be done.

Lastly, I will take only one minute more, Sir, I am not at all happy to criticise; I only want to draw the attention of the Treasury Benches, and particularly the Prime Minister. to this because her name is also taken in all these affairs. They say that the money is collected for party affairs. Mr. Pesi Tata who is the agent for collecting money on behalf of liquor vendors, is reported to have said in Bombay that when Kisan Rally was held, he was asked to pay Rs. 35 lakhs to the railway authorities. From where this money will come? He said, "I get the quota; so I have paid this money". So, Sir. this is political corruption which is going on. For heaven's sake find out, through your Income Tax Department, whether these people who have paid the money to the various trusts, to the cooperators, the Chief Minister or anybody who has formed a trust either in Maharashtra or anywhere in the country, have paid any income-tax. Then you will be doing the greatest service to the nation. Otherwise don't raise this sycophants' army. It will not be of any use for the country or to Indira Gandhi.

श्री कल्पनाथ राय : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो इनकम टैक्स अमेंडमेंट सरकार लाई है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस समर्थन के पहले मैं कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में सरकार इनकम टैक्स अमेंडमेंट के लिये बहुत सा काम कर रही है। लेकिन इस बिल पर बहस करने के पहले हमारे आदरणीय मित्र श्री कुलकर्णी जी ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनका जवाब देना जरूरी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा तो कहना है कि महाराष्ट्र की अल्कोहल इंडस्ट्री जो है उसको नेशनलाइज्ड कर लेना चाहिए और इसको प्राइवेट पार्टी के हाथ में नहीं जाना चाहिए।

[उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी) पीठासीन हुए] महाराष्ट्र को शुगर लाबी और महाराष्ट्र का अल्कोहल यह ब्लैक मनी के जनरेशन का मूल कारण है। उपसभाध्यक्ष महोदय, इन लोगों को श्री अंतुले की फैसिलिटी छोड़ गया है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा हूं कि हिन्दुस्तान में कितने ट्रस्ट हैं और उन ट्रस्टों के कौन-कौन से नेता मालिक हैं। मैं महाराष्ट्र में भी जानता हूं कि बारामती खेतीहर ट्रस्ट श्री शरद पवार का एक करोड़ रुपये का है, श्री रजनी पटेल का ट्रस्ट करोड़ों रुपये का है और श्री वाई० बी० चौहान जो है उनका नाम ढाई सौ करोड़ रुपये का ट्रस्ट है।

श्री राम लखन प्रसाद गुप्त (बिहार) : वह आपकी पार्टी में मिल गये।

श्री कल्पनाथ राय : मैं कहता हूं।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : हम लोग जानते है कि इस समय कांग्रेस के सेक्रेटरी बोल रहे हैं इसलिये कम से कम वाई० बी० चौहान जैसे करप्ट आदमी को आपके दल में नहीं लिया जायेगा, आप यह डेक्लेयर कर रहे हैं, अब यह मालूम हो गया कि ढाई करोड़ रुपये के चोर को कांग्रेस में नहीं लिया जायेगा।

श्री कल्पनाथ राय : उपसभाध्यक्ष महोदय, शाही जी पार्लियामेंट के मेम्बर हैं और मैं चाहता हूं कि आप उसी के अनुकूल बोलें। मैं कहता हूं कि चौधरी चरणसिंह ने ट्रस्ट बनाया 84 लाख का, श्री दीनदयाल उपाध्याय ट्रस्ट बनाया गया सारे ट्रस्ट जो बने हैं और हिन्दुस्तान की जितनी पार्टीज हैं उनके जितने बड़े बड़े नेता हैं सबके नाम ट्रस्ट हैं . . . (**व्यवधान**)

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) : अंतुले इतने बड़े नेता हैं क्या। अंतुले चपरासी के बराबर हैं।

श्री कल्पनाथ राय : बात सुनिये, आप वैसी ही बात कीजिए जैसे दूसरों के साथ आप करना चाहते हैं। आप कहते हैं इन्कम टैक्स, उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछली बार देश के जमाखोरों, चोरबाजारियों और तस्करों के खिलाफ इमरजेंसी के दौर में जितने कड़े कदम उठाये गये थे और मुझे अच्छी तरह से याद है जब आपकी पार्टी पावर में आई तो आप लोगों ने उन जमाखोरों को, रैकेटीयर्स को और तस्करों को गले लगाया, उनको तिलक लगाया और उनको कहा कि अब तुम पवित्र हो गये। जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति जो देश के माने हुए नेता थे उनको भी इसमें इन्वाल्व किया कि हाजी मस्तान को तिलक दें कि अब ये हिन्दुस्तान के श्रेष्ठ नागरिक हो गये है . . . (**व्यवधान**) कांग्रेस की सरकार ने हिन्दुस्तान के जितने जमाखोरों, ब्लैक मार्केटियरों और तस्करों को जेलों में डाला मैं जानना चाहता हूं कि पिछले तीन साल के अंदर तुमने क्या किया? शर्म की बात होनी चाहिए कि तुमने तो. साल के अंदर कुछ नहीं किया . . . (**व्यवधान**)

श्री सत्यपाल मल्लिक (उत्तर प्रदेश) : जितको जेल में डाला था उनको आपने . . . (**व्यवधान**) देना शुरू कर दिया . . . ।

श्री कल्पनाथ राय : मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। यह चरित्र हत्या करना, आप इतने बेईमान और भ्रष्ट हैं मैं उन बातों को कहना नहीं चाहता इस पार्लियामेंट के अंदर। अब ट्रस्ट में मनी क्यों है। ट्रस्ट की मनी पर इन्कमटैक्स नहीं लगेगा, कोई उस पर टैक्स नहीं लगेगा और मनी देता कौन है। जो बड़े बड़े पूंजीपति होंगे या जो बड़े-बड़े लोग होंगे वे ही पैसा देते हैं और . . . (**व्यवधान**) जितने ट्रस्ट अब बने हैं। अगर आपने एक रुपये की चोरी की किसी ने 10 रुपये की चोरी की तो चोर दोनों हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों ने क्या 84 लाख रुपया ट्रस्ट बनाने के लिए चौधरी चरण सिंह को दिया। तुम्हारी सरकार थी तो तुमने सत्ता

का इस्तेमाल करके फरीदाबाद और गाजियाबाद के बड़े-बड़े व्यापारियों से करोड़ों रुपया इक्कट्ठा किया था... (व्यवधान) ऐसा ही नहीं...

श्री रामेश्वर सिंह : आप मेरी बात सुनिये । चौधरी चरण सिंह को जो पैसा मिला वह किसानों से मिला...मैं साबित करता हूं... (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : रामेश्वर सिंह, बैठो, बहस मत करो ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के के अंदर कितनी इन्क्वायरियां हुईं । अट्ठाईसों इन्क्वायरी कमीशन बैठे । मगर देश की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी अग्नि परीक्षा देकर बाहर आयीं । जो इन्क्वायरी कमीशन मोरारजी भाई और चरण सिंह ने बिठाये उनकी क्या फाइंडिंग्स हैं... (व्यवधान) चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ...

श्री रामेश्वर सिंह : यह जनता पार्टी के लोगों की नालायकी... (व्यवधान) जिसके कारण इंदिरा गांधी आज आयी हैं ।

श्री कल्पनाथ राय : मैं कहना चाहता हूं कि वैद्यलिंगम कमीशन की रिपोर्ट क्या लिखती है ? वैद्यलिंगम की रिपोर्ट लिखती है कि चौधरी चरण सिंह... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : हिम्मत हो तो मुकदमा चलाओ... (व्यवधान) सीताराम केसरी जो आप मुकदमा चलावाओ... (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : वैद्यलिंगम क्या लिखता है कि हिन्दुस्तान के प्राईम मिनिस्टर की पत्नी घूस लेती है । इसके बावजूद तुम राजनीति में रहना चाहते हो और बहयाई की हद है...हमको पीटो, हमको पीटो... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह : जा हो मुकदमा चलाओ... (व्यवधान) चरण सिंह पर मुकदमा चलाओ ।

श्री कल्पनाथ राय : शाही जो आप कहां चले गये । मैं चरित्र हत्या की राजनीति में विश्वास नहीं रखता, वैद्यलिंगम लिखत है... ।

मोरारजी देसाई और उसका बेटा और प्रिंसिपल सैक्रेटरी ने देश के कई टन सोना को बेच करके मुल्क के सोने के खजाने को खाली किया ।

जो खुद इतने बड़े बेईमान हैं, जिन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जजों के फैसले हो चुके है, उनको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करने पर ।

यह एक छोटा सा बिल है... (व्यवधान) छोटे से बिल में जो... (व्यवधान)

SHRI SANKAR PRASAD MITRA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, if this kind of thing goes on, we have to come to the conclusion that about 200 commissions of inquiry would be required in this country.

SHRI KALPNATH RAI: Respected Sir, I agree with your opinion. But you should also ask those Members to confine themselves to the subject when they are speaking. And this gentle Vice-Chairman, who is presiding, himself attacked the hon. Chief Minister of my party.

SHRI RAMESHWAR SINGH: Corrupt Chief Minister. जिसने पैसा लिया है... (व्यवधान)

SHRI KALPNATH RAI: I want to ask my friend Mr. Rameshwar Singh . (*Interruptions*). Mr. Rameshwar Singh may not know English, he may be a dacoit, but so long as he is a Member of Parliament he is honourable. I would not say anything other than this. What the hon. ex-Chief

[Shri Kalp Nath Rai]

Justice and now a Member of Parliament has said is correct.

श्री रामेश्वर सिंह : कांग्रेस पार्टी में लोगों ने . . . (**व्यवधान**) . . . अंतुले को तो आप लोगों ने चुना . . . (**व्यवधान**)

श्री कल्पनाथ राय : श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि आप अंतुले की बात कहते हैं, क्या शरद पवार से भी कोई करप्ट चीफ मिनिस्टर हिस्ट्री में हुआ है . . . ? (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Kalpnath Rai, just a minute. I am not interrupting you. When I am the Presiding Officer, I cannot stop you. You can say whatever you like and I do not want to stop you at all. But when I go back to my seat, I will say whatever I want to. So you go ahead. I am not interrupting you.

SHRI KALPNATH RAI: I can say that Sharad Pawar was a politically corrupt Chief Minister, a defector, and he had built more than ten trusts and collected crores of rupees. He is the most corrupt Chief Minister in the history of India. I demand a commission of inquiry to go into the question of all the money collected by Sharad Pawar, the money he collected in the form of trusts.

श्री रामेश्वर सिंह : श्री भजन लाल . . . (**व्यवधान**) भजन लाल . . . (**व्यवधान**)

SHRI KALPNATH RAI: He himself created a trust. Talk of Chaudhry Charan Singh. Don't talk of Bhajan Lal. (*Interruptions*). I know Rameshwar Singh and how to reply to him.

अब मैं इन बातों को छोड़ कर इनकम-टैक्स के संबंध में कुछ बात करना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविंद गणेश कुलकर्णी) : अब सही निर्णय लिया।

श्री कल्पनाथ राय : आज जिस दौर में देश गुजर रहा है, इस दौर में जिस गम्भीरता और जिस राष्ट्रीय मतैक्य की आवश्यकता है, इसमें सभी दल के लोग मिल कर इस मुल्क की अर्थ-व्यवस्था को बचाने की दिशा में सोचें, वह आज इस पार्लियामेंट में देखी नहीं जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-स्फीति का शिकार दुनिया के सारे मुल्क हैं और दुनिया की जो मजबूत व्यवस्थाएं भी हैं, वे भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-स्फीति की शिकार हैं और हिन्दुस्तान जैसा गरीब देश जो एक विकासशील देश है, एक डिवैलपिंग कण्ट्री है, जिसकी जनसंख्या दुनिया में जबरदस्त बढ़ी हुई है, उस मुल्क की अर्थ-व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिए मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए ठोस और समयबद्ध कदम उठाने होंगे . . . (**व्यवधान**)

श्री रामेश्वर सिंह : तीनों मिल करके भी नहीं कर सकते . . . . (**व्यवधान**)

श्री कल्पनाथ राय : इण्टरनेशनल इन्फ्लेशन, बैलेंस आफ पेमेंट, या इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट यह चीजें अगर . . . . . रामेश्वर सिंहजी आप दखल न दें, तो ठीक होगा इसलिए मैं कहता हूं, आज प्रोडिक्टव्ह इकानामी की देश को आवश्यकता है, और वांचू कमेटी के रिकमण्डेशंस के आधार पर डेवलपिंग कन्ट्री लाइक इंडिया में एक परेलल इकानामी चल रही है। उसको ही रोकने के लिए वांचू कमेटी ने कुछ सुझाव दिए हैं। मैं सरकार से चाहता हूं उस पर आप गौर करें।

हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि हम शुगर क्यों इम्पोर्ट करें, व्हीट क्यों इम्पोर्ट करें, सीमेंट क्यों इम्पोर्ट करें? हमारे देश के धरती के पेट में इतनी दौलत है, इतनी ताकत है कि हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तब हम अपने देश में क्यों इम्पोर्ट करें? कारण क्या है? यदि हम अपने देश के किसानों को, खेत में काम करने वाले लाखों लाख किसानों

को यदि उनकी पैदा की हुई चीजों के रेम्युनरेटिव प्राइसेज देंगे तो निश्चय ही हमारे मुल्क का उत्पादन बढ़ेगा और हमको बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। हमारे देश में इतना डिपाजिट है लाइम, जितना डिपाजिट रोहतास जिले में, भागलपुर के पास है, उससे हम सारे एशिया को सीमेंट सप्लाई कर सकते हैं। आप जानते हैं, हमें शुगर इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, जनता पार्टी की जन-घाती और राष्ट्र-घाती, किसान घाती नीति के कारण विदेश से आयात करना पड़ रहा है। तो प्रश्न यह उठता है कि जिन चीजो की बहुतायत है, जो हमारी धरती पर पैदा हो सकती है उन पर हमें आत्म निर्भर होना चाहिए हमें ऐसी पालिसी बनानी चाहिए कि जितना जो कमाता है, 100 में 60 हिस्सा सरकार ले ले। मैं सरकार से चाहता हूं वह इस कर-नीति को अपनाए ताकि दो तरह के कमाने वाले लोग अपने पास पैसा न रखें। मैं तो सरकार से चाहूंगा कि जो व्यक्ति 100 रु० कमाता है उसको कम से कम 50 रु० अपना पैसा रखने का मौका दिया जाना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Please conclude.

श्री कल्पनाथ राय : मुझे बोलने दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Rou have to conclude now.

श्री कल्पनाथ राय : जो आप चाहते हैं वही सब बोला जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): I have got no time. I have to complete this in record time.

अच्छा, दो मिनट और ले लो।

श्री कल्पनाथ राय : दूसरी बात मुझे यह निवेदन करना है कि इस मुल्क की इकानामी को प्रोडक्शन ओरियेंटेड बनाया जाय और जितना फजूलखर्ची का सामान इस मुल्क में पैदा होता है उसको बंद किया जाए। इस मुल्क के अंदर फिजूलखर्ची की चीजें न प्रोडयूस की जाएं न ही उनका कंजम्पशन अलाऊ किया जाय जब तक इस मुल्क में कैपिटल नहीं हो जाता है। जो मुल्क में दौलत छिपी हुई है ब्लैक मनी, उसको समाप्त करने की जरूरत अगर सरकार नहीं समझती है तो हम कदापि इस मुल्क की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय आज पूरी दुनिया के पैमाने पर 5600 करोड़ रु० का तेल हमें विदेशों से खरीदना पड़ रहा है यानि अंतर्राष्ट्रीय तनाव की परिस्थितियों के कारण 600 करोड़ से ज्यादा डिफेंस पर, 6200 करोड़ रुपये हमारी इकानामी पर बोझ पड़ा है। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हमें ऐसी इकानामी की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हम दुनिया के बाजार अपने देश का सामान ज्यादा से ज्यादा बेचें और कम से कम सामान हम अपने मुल्क में खरीदें ताकि हमारा बैलेन्स आफ पेमेन्ट घटे और हम कैपिटल फार्मेशन करके एक मजबूत अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करें ताकि हमारे देश का स्वरूप आधुनिक, विकासशील, समाजवादी देश, इन्दिरा गांधी के सपनों का शक्तिशाली देश बना सकें।

श्री राम लखन प्रसाद गुप्त : (बिहार) उपसभाध्यक्ष महोदय यह जो इनकम टैक्स अमेंडमेंन्ट बिल लाया गया है मैं इस का स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि मंत्री जी ने ब्लेक मनी निकालने की बहुत कुछ कोशिश की है। 10,000 रुपये तक जिसमें ब्याज भी है, [उसका पेमेंट कहीं से भी हो—बैंक या कोआप-

[श्री राम लखन प्रसाद गुप्त]

रेटिंग बैंक या फर्म से – तो बैंक के द्वारा एकाउंट पेयी हो, या बीयरर बाण्ड के लिए जैसा उन्होंने किया है, यह बहुत ही अच्छी बात है। ।

परन्तु मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचना चाहूंगा कि क्या यह पर्याप्त है? जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है यह बिल्कुल ही पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे नान–बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स हैं जहां से रुपये का लेन-देन होता है, पर उनको इस में नहीं लिया गया है। कलकत्ते में एक संचिता कह कर फर्म है जो 48 परसेंट इन्टरेस्ट देती है। 12 परसन्ट लिखा जाता है, परन्तु 48 परसेन्ट इन्टरेस्ट लोगों को देती है और लोग वहां पर रुपया जमा करते हैं। ऐसे नान-बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स हैं। उधर भी ध्यान देना चाहिए ।

दूसरी चीज यह है कि इनकम टैक्स की वर्किंग बहुत ही असन्तोषजनक है। 77 में जो इन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट पास किया उसके तहत जो इम्मूवेबिल प्रापर्टी को जब्त करने की बात थी उस में 2097 मामलों में कार्यवाही हुई और उसमें केवल 4 जायदाद जब्त की जा सकीं । इसी तरह 80 में 5400 पर कार्यवाही हुई और उस में केवल एक प्रापर्टी जब्त हो सकी है। हम सोच सकते हैं कि यदि यह स्थिति है तो इसके पीछे खर्च कितना है और उससे उपलब्धि कितनी मिल पाती है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचूंगा कि वे देखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ठीक काम करता है या नहीं करता है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगा — बहुत ही कम अफसरों को छोड़ कर – कि इनकम टैक्स के अफसर they their own income fix यह उन की मर्जी पर है कि कितनी इनकम करें। आज चारों तरफ भ्रष्टाचार का वातावरण है। ऐसा क्यों हो गया है। पिछले 32 वर्षों के युग में भ्रष्ट राजनीतिज्ञ और भ्रष्ट नौकरशाह का मेल हो गया है, एलाइनमेन्ट हो गया है और एलाइनमेंट हो जाने के कारण वे देश को लूट रहे हैं। हमारे पूर्ववक्ता श्री कल्पनाथ राय ने कहा कि व्यापारियों से लेते हैं, लेकिन व्यापारियों से इतना रुपया नहीं आता है। अब तो सरकार के रुपयों लिये जाते हैं । अगर कोई ठेकेदार है, कहीं पर टेंडर है तो उसमें शेयर बांटते हैं – भ्रष्ट पोलिटीशियन और भ्रष्ट नौकरशाह मिल जाते हैं।

जैसा आप ने अपने भाषण में कहा था, बिहार का वातावरण बहुत खराब हो गया है। आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि वहां पर नेशनल हाइवे 31 और मनसी रेलवे स्टेशन को बचाने के लिए गंगा में बोल्डर डाला जाता है, करोड़ों रुपये उस में खर्च होते हैं, किन्तु मुश्किल से दस परसेंट का काम होता है, 90 परसेंट रुपया ठेकेदार और इंजीनियर बांट लेते हैं। अभी एक केस आया जिस में एक इंजीनियर ने कहा कि मेरे पास एक लाख रुपये का चेक है, जो मुझे 60 हजार देगा मैं उसको 1 लाख का चेक दे दूंगा। न काम हुआ, न बोल्डर की सप्लाई हुई लेकिन 1 लाख का चेक उस ने ठेकेदार को दे दिया और 40 हजार रुपये रख लिये। आज ऐसा वातावरण है कि चाहे कोई इंजीनियर हो, पी० एच डी या पी० डब्ल्यू० डी० का इंजीनियर हो 45 हजार से कम में उसकी बदली नहीं होती है–45 हजार से ज्यादा जितना हो।

बिहार के मिनिस्टर करोड़पतियों से कोई कम नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि अगर आप समाज में ब्लैक मनी को रोकना चाहते हैं तो आप ऐसे पोलीटीशियन और ऐसे नौकरशाह, जिन की आज अट्टालिकाएं बड़े बड़े नगरों में खड़ी हैं उन सारी अट्टालिकाओं के ऊपर इनक्वायरी बैठाइये। पोलीटीशियन्स के ऊपर इनक्वायरी बैठाइये अगर उन की आमदनी के अनुपात से अधिक रुपया उन के पास है। अगर यह दो रास्ते आप लें तो इस से आम जनता में विश्वास होगा, राजनीतिज्ञों में भ्रष्टाचार कम होगा और उस के रहनसहन में सादगी भी आयेगी। इस लिए मेरी यह मांग है कि आप इस तरह की इनक्वायरी सेल बना कर इनक्वायरी शुरू करें।

दूसरी मेरी मांग है, जैसा वांचू कमीशन ने कहा है कि डिमोनीटाइजेशन आप करें और सौ रुपये के नोट को समाप्त करें। सौ रुपये के नोट की आज जरूरत नहीं है, इस को आप समाप्त करें तो इस से बहुत लाभ हो सकेगा। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री लाडली मोहन निगम : उपसभाध्यक्ष जी, अगर खजानमंत्री जी की नीयत साफ है कि इस बिल से जो काले धन का चलन है उस को रोका जाय और जो बेनामी हवाले के तरीके से लेन देन होता है उस को रोका जाय तब तो सही है लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों बातों की झलक मुझे इस में मिलती नहीं है। रोग कहीं और है और इलाज कहीं और हो रहा है। इलाज हम कहीं और ढूंढ रहे हैं। हिन्दुस्तान में जिपना फैशन और विलासिता का जीवन आज चारों तरफ दिखायी दे रहा है उस को आप इस से रोक नहीं सकते। इस में दो तीन चीजें खटकती हैं। आप ने कहा है कि दस हजार से ऊपर की जो रकम देनी है तो वह चेक से देनी चाहिए और वह उस को ही देनी चाहिए कि जिस के नाम चेक हो। लेकिन उस आमदनी का आप क्या करेंगे कि जो आज हिन्दुस्तान में हवाले के तरीके से की जाती है। शायद मंत्री जी को यह मालूम हो कि अब तो एक नया धंधा शुरू हो गया है। आज एक आदमी जिसने अपना इन्कम टैक्स 40 हजार का दिखाया है वही अगले साल एक लाख रुपये का दिखा देता है। इन्कम टैक्स अफसर अगर कहता है कि यह कहां से लाये तो उस का कहना होता है कि इस पर जितना टैक्स लगता है वह ले लो। मतलब यह है कि उस को कोई एतराज नहीं होता और ऐसे कितने ही आदमी को बड़े फर्म्स ने बिठा रखे हैं। पैसे वालों ने अपने कर्मचारियों के नाम से इन्कम टैक्स में रिटर्न भरवा दिये हैं और एक लाख की आमदनी आप ने उस की मान ली तो आइन्दा के लिये एक लाख पर एक हजार रुपया उस को घर बैठे मिलता रहता है और यह उस की सफेद आमदनी हो जाती है। इस को आप कैसे रोकेंगे। सवाल यह है कि ईमानदाराना तरीके से आप हिन्दुस्तान में काले धन पर रोक नहीं लगाना चाहते हो ताकि गलत तरीकों से लेन देन न हो तो एक चीज हिम्मत के साथ आप को करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में आप के बनाये कानूनों पर सही तरीके से अमलदरामद हो तो उस के लिये जरूरी है कि हिन्दुस्तान में आप खर्च पर कोई सीमा लगायें। जब तक हिन्दुस्तान में खर्च की सीमा नहीं बंधेगी हिन्दुस्तान में काले धन को रोका नहीं जा सकता। अगर आज हम खर्च की सीमा निर्धारित कर दें, वह चाहे 5 हजार हो या 2 हजार हो या दस हजार हो, आप जो चाहे रखें लेकिन अगर एक मर्तबा आप कानून बना दें कि इस से ज्यादा खर्च नहीं किया जा सकता तो किसी आदमी की जो दो नम्बर की कमायी है उस को वह कहां ले जायेगा। खर्च करने पर उस को आप

[श्री लाडली मोहन निगम]

तत्काल पकड़ सकते हो और इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते है कि ईमानदाराना तरीके से हिन्दुस्तान में काले धन का चलना रुके तो खर्च की सीमा बांधने वाला बिल, कानून आप लाओ और दूसरी चीज यह है कि हिन्दुस्तान में जो भी पैसा बनता है अगर कोई आदमी उसे विदेश में जमा कराता है तो उस की सारी संपत्ति को आप हिन्दुस्तान में जब्त कर लो। जो भी उस के पास है। ऐसा होने पर ही आप कुछ कर सकते हो। आदमी यहां रुपया कमाता है, यहां संपत्ति बनाता है और जब उसको लगता है कि और ज्यादा यहां नहीं बनाया जा सकता तो दो नम्बर के पैसे को वह विदेशों में रख देता है। इस पर एक लम्बी बहस हो सकती है। साफ सवाल है कि हिन्दुस्तान में कोई आदमी विदेश के बैंक में अपना पैसा जमा करता है और व्यापार करता है तो उसे आप पकड़ सकते हो, लेकिन अगर कोई ऐसा भारतीय नागरिक हो जो आप की जानकारी के बिना ऐसा करता हो तो उस की आप संपत्ति जब्त करो, उस का नागरिकता का अधिकार छीन लो तभी मैं समझूंगा कि आप ईमानदार हो, नहीं तो नहीं।

एक और बीसरी बात कह कर मैं अपनी बात खत्म करुंगा। आप को हिन्दुस्तान में कहीं न कहीं बराबरी की कोई न कोशिश करनी होगी, कोई सीढ़ी बनानी होगी और अगर ऐसा करना है तो उस के लिये मेरा पहला सुझाव है कि आप हिन्दुस्तान में खर्च की सीमा बांधो। दूसरे हवाले का और बेनामी का जो लेन देन होता है उस पर रोक लगाओ और उस के लिये आप यह करो कि जितने लोग हैं उन के और उन के परिवार की जो परिसंपत्ति है उस का आप को आयजा लेना पड़ेगा और तीसरे यह कि हिन्दुस्तान के सार्वजनिक जीवन में जो आदमी उतरेगा उस को अपनी परिसंपत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी और उस की कोई भी आदमी जांच कर सकेगा जैसे अदालत में किसी केस को कोई आदमी देख सकता है। अगर बिरला के किसी कारखाने की मैं जांच करना चाहूं तो आप के यहां कोई कानून नहीं है कि इंकम टैक्स आफिस में जा कर मैं उसकी असलियत का पता लगा सकूं। अगर आप खाली क्लाइंट और अफसरों के बीच में यह मामला रखोगे तथा उसको आम आदमी के बीच का मामला बनाओगे और खर्च की सीमा बन्दी करोगे, विदेशी बैंकों में जिन आदमियों का पैसा हो, उसकी हिन्दुस्तान में सम्पत्ति की जब्ती करोगे तो कुछ हो सकता है। इसके साथ ही तीसरा सुझाव जो मैंने आपको दिया है वह है हिन्दुस्तान के सार्वजनिक जीवन में जो लोग पदार्पण करना चाहते है उनकी सम्पत्ति के बारे में भी आपको कहना पड़ेगा। ये तीन बातें कर दो तो मैं आपके इस बिल का समर्थन करने के लिए तैयार हूं आप जानते हैं कि जिसको बेयरर बांड आप कहते हो उसको आप बदल नहीं सकते हो। (समय की घंटी)

श्रीमान् मैं खत्म कर रहा हूं। कोई भी आदमी आज अपने बेयरर बांड को बेनामी तो बेच ही सकता है। कोई उससे पूछने नहीं जाता है कि कहां से आया। मैंने खरीदा है, कल्पनाथ जी को दे दिया, कल्पनाथ जाकर उसका भुगतान करा सकते हैं। इस वास्ते जिस मंसा से आपने यह बालू किया है, जब तक बेयरर बांड को आप बेचने से रोकने की कोशिश नहीं करते हो यह काला धन समाप्त नहीं होने वाला है। इसको आप रोक दे। इतना ही मेरा निवेदन है।

SHRI DIPENDRA BHUSAN GHOSH (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I welcome this amend-

ment to the Income-Tax Act. But I am doubtful whether, by bringing forward this small amendment, the objective of arresting the proliferation of black money can be achieved at all. Because, Sir, in the Income-Tax Act itself there is already a provision in regard to business expenditure. Under section 43A(3) of the Act, Sir, there is a provision which empowers the Income-Tax Officer to examine payments exceeding Rs. 25,000 made in respect of any expenditure and disallow it if it is not made by a crossed cheque or by a crossed bank draft. May I inquire from the honourable Minister of State for Finance whether this prohibitive provision under this section was in any way helpful in arresting the proliferation of black money? The fact that the Government had to introduce the much-publicised Voluntary Disclosure Scheme in 1975 and the Special Bearer Bonds recently proves beyond doubt that tiny steps like the one just before us for consideration will not result in achieving the desired objective of arresting the proliferation or operation of black money, but will only act as a propaganda gimmick of the Government.

Sir, I may also be permitted to draw the attention of our honourable Minister to another section in the Income-Tax Act and that is section 143(1) of the Act. The provision as it stands today was first introduced to be operative from the 1st of April 1971, that is, a decade back. It was given wide publicity under the nomenclature "Summary Assessment Scheme". According to this Scheme, an assessing officer is empowered to examine and finalise the assessment of an assessee without asking for any details in regard to the production process, etc. from the asessees. Initially, this scheme was made applicable... (*Time Bell rings*). Sir, just one minute. This is a very important point.

Initially, this Scheme was made applicable only in the case of people who had a taxable income below Rs. 25,000. But, during the last ten years, this has been exceeded and it has rather increased to the tune of Rs. 1 lakh. Sir, according to the Government, today, a person whose taxable income is Rs. 1 lakh is a small man and, according to this provision, he is required to submit a return, but the Income-Tax Officers are not required to assess or scrutinise those returns. So, Sir, may I ask whether the repayment of the deposit amounting to Rs. 10,000 made by crossed cheque or draft will have any effect if the Income Tax Department refuses to scrutinise the details of the investment and repayments? I feel that this Bill introduced by the hon. Finance Minister will fail to arrest the prevalence of black money operations in our country. Sir, I will request the hon. Finance Minister to go into the details of causes for which the black money is created, proliferated and operated in our country. He should take effective steps for arresting it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): That is all right. Mr. Krishnan.

SHRI U. R. KRISHNAN: Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Bill. In India black money and tax evasion are playing havoc in our developing economy. According to the statistics available, at least Rs. 30,000 crores of black money is in operation. I do not know how this black money has developed to a huge amount because of the tax evasion. It is also an admitted fact that in India the highest taxation is there. That is why the people would like to evade tax. Sir, in order to avoid tax evasion and to curb black money, I would suggest demonetisation. At least the hundred rupee notes should be demonetised.

Sir, in this connection I would also like to mention that Mr. Karunanidhi, who was indicted by the Sarkaria Commission for looting Tamil Nadu and amassing huge wealth. He has deposited crores of Rupees in Singapore and other places and started

[Shri U. R. Krishnan]

joint collaboration with a Joint Managing Director of a cement company, and established a palm oil company at Singapore. He has overnight changed more than Rs. 10 lakhs in smaller denominations with the help of an IAS officer. Even now he is giving black money for creating law and order problem in Tamil Nadu and disturb the Government of Tamil Nadu. These things should be investigated. (*Time Bell rings*).

Regarding this Bill I would like to know whether this cheque or draft system is going to be effective in the case of some of the institutions who know how to cheat the Government and who even advise the parties to deposit amounts which will not be more than Rs. 10,000 or indulge in *benami* transactions?

With these words, Sir, I conclude.

DR. MALCOLM S. ADISESHIAH (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, I also support the Bill, the Income-Tax (Second Amendment) Bill, 1981, for consideration and return. I agree with my colleagues, Mr. Ghosh and Mr. Krishnan. The two provisions made here are for payee cheques to be used for all payments above Rs 10,000, and for redemption of Bearer Bonds as part of the total programme to control black money. I want to say a few things about black money. First of all, there is no such thing as black money sector and white money sector. As Mr. Krishnan was saying, both black money and white money are so mixed up that we cannot really distinguish that this is black money sector. About everything, almost for every important transaction, both black money and white money are being used. This should be brone in mind. Second there are four sings of black money. First, when the taxable value of a transaction is below the actual value, black money is in operation. Secondly, the rate of return is much higher in the black money sector than in the white money sector. That is why, black money is being used. Thirdly, the income velocity of black money is much higher than the income velocity of the official sector. Lastly, when the prices of gold and land are rising faster then the general price rise, we know that black money is in operation. This black money operation is frustrating everything that the Government is trying to do to control inflation, to bring about development and to improve the condition of our poor people. The reasons for the operation of black money are inflation which is now slowly coming under control, but it is still there, controls which are not needed and punitive taxation. I think while supporting this Bill, we stand all come together in asking the Government to take the ultimate remedy against black money which is demonetisation.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Do you want to reply to the Statutory Resolution?

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: No, Sir.

SHRI SAWAI SINGH SISODIA: I am very thankful to the hon. Members who have participated in the debate. Generally, all the hon. Members have directly or indirectly suported the measure which is before the House. Mr. Vice-Chairman, Sir, including yourself all the other Members have supported the Bill. You have raised many points which may not be relevant and my friend, Mr. Kalpnath Rai, has replied to some of them in the same language and with the same force. Sir, I will not like to take up the time of the House in replying to the political points which have been raised in your speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Take note of all the points. That is all right.

SHRI SAWAI SINGH SISODIA: That is noted and specially your speech I have completely noted. One point

raised was that out of 393 recommendations contained in the Final Report of the Wanchoo Committee, 326 recommendations have been accepted and 317 recommendations have been implemented. Out of these recommendations, there are very few recommenations still under consideration and a large number of them relates to administrative matters. Regarding the point made by Shri Ram Lakhan Gupta that most of the non-banking institutions would be covered by the new provision, it is because these are all organised in companies and cooperative societies and this new amendment will cover all the other associations of persons or individuals and will make the provisions very difficult to administer. I will take one more minute in giving the statistics because many Members have touched this topic of acquisition of the immovable property by the Income-tax authorities. In the financial year 1978-79, the number of notices issued was 4060 and the number of properties acquired was two. The compensation paid was Rs. 7,59,000. Similarly, in 1979-80, notices were issued in 5382 cases. In 1980-81, this number was 5084. 16 immovable properties have been acquired by the Income-tax Department. I think I need not take more time of the House because all the hon. Members have welcomed and supported this measure.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): I am now putting the Resolution to vote. The question is:

"That this House disapproves the Income-Tax (Amendment) Ordinance. 198 (No. of 1981) promulgated by the President on the 11th July, 1981."

The motion was adopted.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): No, no.

SHRI V. GOPALSAMY: Please allow me one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): There is no procedure like that, and not at this stage.

SHRI V. GOPALSAMY: Please allow me one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): I fully agree that you want to say something. When the Third Reading comes, I will you for a minute. There is a procedure for it.

Now, I will put the Bill to vote. The question is:

"That the Bill further to amend the Income-tax Act, 1961, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): We shall now take up clause-by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 7 were added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SAWAI SINGH SISODIA: Sir, I beg to move:

"That the Bill be returned."

The question was proposed

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Gopalsamy, just two minutes, please.

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, the hon. Mr. Krishnan has made some allegations against my party leader, the former Chief Minister of Tamil Nadu. But, Sir, those allegations are baseless and malicious. And I would also like to put it on record that those allegations should be expunged from the proceedings of this House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): I am sorry, I am not going to do that.

SHRI V. GOPALSAMY: Sir, I would also like to know from the hon. Minister whether any person's property or house which was attached by the Income-tax officials can be sold. I want to know this because the Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M. G. Ramachandran, whose house was attached by the Income-tax officials was sold by him to his wife. To whom he has sold? He has sold it to his wife. I want to know whether the Minister will allow any other person to do that things. The Chief Minister of Tamil Nadu sold the house which was attached by the Income-tax officials to his wife. And now they are coming and making false allegations. The allegations made here by Mr. Krishnan cannot at all be proved.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): For your information, I am not going to expunge anything.

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Now, Shri Bagaitkar. You have two minutes, please.

श्री सदाशिव बगाईतकर (महाराष्ट्र) : श्रीमन्, मेरा इतना ही नम्र निवेदन है कि *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): We have allegations galore in this House. Don't worry about it.

श्री सदाशिव बगाईतकर : माननीय मंत्री जो अमेंडमेंट लाये है अगर उनको जड़ में रह जायें . . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविंद गणेश कुलकर्णी) : जल्दी चलिए। ऐसा न हो कि दो घंटे तक बैठना पड़े।

श्री सदाशिव बगाईतकर : दलामल टैक्स में जो रेड हुआ था इनकम टैक्स विभाग द्वारा और जिसमें झेनिश ट्यूब कम्पनी के लिए फ्लैट खरीदा था, 65 लाख रुपये का उसमें से 35 लाख रुपये जो दिये गये वे लीगल तरीके से दिये गये लेकिन 31 लाख रुपये वह अलग तरीके से, अंडर टेबल दिये गये तब से यह मामला चला आ रहा है मेरी यह जानकारी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जिस तरह से रेड किये जाते हैं और बाद में उनका जो घटनाक्रम रहता है, उसको अखबार में पढ़ने के सिवाय और आगे क्या होता है इसका पता नहीं चलता है। जो आंकड़े सामने आये हैं, अटैचमेंट वगैरह के उनसे साबित होता है कि इसमें करप्शन होता रहा है। इसलिये आप इसको असल तरीके से अमल में लाने का आश्वासन यहां पर दें, इतना ही मेरा कहना है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): The question is:

"That the Bill be returned."

The motion was adopted.

THE BURMAH OIL COMPANY (ACQUISITION OF SHARES OF OIL INDIA LIMITED AND OF THE UNDERTAKINGS IN INDIA OF ASSAM OIL COMPANY LIMITED AND THE BURMAH OIL COMPANY (INDIA TADING) LIMITED) BILL, 1981

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): We shall now take up the next Bill of Shri Sethi.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): What about the Special Mentions?